



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खंड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 221 ]  
No. 221 ]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 3, 1997/चैत्र 13, 1919  
NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 3, 1997/CHAITRA 13, 1919

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 अप्रैल, 1997

का. आ. 291(अ).—जबकि ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स (इसके बाद इसे ए. टी. टी. एफ. कहा गया है) का घोषित लक्ष्य पूर्वोत्तर क्षेत्र के अन्य सशस्त्र अलगाववादी संगठनों से समझौता करके सात राज्यों यथा त्रिपुरा, असम, मणिपुर, मिजोरम, नागालैण्ड, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश के संघ के एक पृथक राष्ट्र का निर्माण करना और इसके परिणामस्वरूप इन राज्यों का भारतीय संघ से अलगाव करना और इन राज्यों को भारतीय संघ से अलग करने के लिए सशस्त्र संघर्ष जारी रखना और उसके द्वारा इन राज्यों का भारतीय संघ से अलगाव करना है,

जबकि केन्द्र सरकार की राय है कि ए. टी. टी. एफ.—

- (i) विध्वंसकारी और हिंसक गतिविधियों में लिप्त है, जिससे विधि द्वारा स्थापित सरकार की सत्ता को क्षति हो रही है और अपना लक्ष्य पूरा करने के लिए वह लोगों में आतंक और हिंसा फैला रही है,
- (ii) ने अन्य गैरकानूनी संगठनों अर्थात् असम के यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम (उल्फा) और मणिपुर की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पी. एल. ए.) से उनका समर्थन प्राप्त करने के उद्देश्य से संपर्क स्थापित किया है,
- (iii) अपना लक्ष्य हासिल करने के लिए हाल ही में अनेक हिंसात्मक तथा गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल हुआ है जो भारत की प्रभुता और अखण्डता के प्रतिकूल है,

और जबकि केन्द्र सरकार की यह भी राय है कि हिंसात्मक तथा गैरकानूनी गतिविधियों में निम्नलिखित शामिल है :—

- (क) नागरिकों और पुलिस तथा सुरक्षा बलों के कार्मिकों की हत्या,
- (ख) त्रिपुरा में व्यावसायिकों तथा व्यापारियों सहित जनता से जबरन धन ऐंठना,
- (ग) गुप्त/गैरकानूनी माध्यमों से अत्याधुनिक हथियारों सहित बड़ी मात्रा में शस्त्र और गोलाबारूद प्राप्त करना और इन्हें किसी पड़ोसी देश के माध्यम से त्रिपुरा में गुप्त रूप से भेजना,
- (घ) सुरक्षित पनाह, प्रशिक्षण, हथियारों तथा गोलाबारूद की प्राप्ति के उद्देश्य से किसी पड़ोसी देश में शिविर लगाना और उनका संचालन करना,
- (ङ) त्रिपुरा में जनजातीय तथा गैर जनजातीय समुदायों के बीच साम्प्रदायिक दंगे करवाने तथा भड़काने के लिए त्रिपुरा के अन्य जनजातीय उग्रवादी समूहों के साथ संपर्क स्थापित करना और उसे बनाए रखना।

और जबकि केन्द्र सरकार की राय है कि ए.टी.टी. एफ. को उपरोक्त गतिविधियाँ भारत की संप्रभुता तथा अखण्डता के लिए खतरा है और यह एक गैर कानूनी संगठन है,

अतएव, अब गैर कानूनी गतिविधियाँ (निरोधक) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा घोषणा करती है कि ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स (ए. टी. टी. एफ.) एक गैर कानूनी संगम है,

और जबकि केन्द्रीय सरकार का यह भी मत है कि यदि ए.टी.टी. एफ. पर तत्काल नियंत्रण नहीं लगाया जाता है तो उसे निम्नलिखित कार्यों के लिए अवसर मिल जाएगा—

- (i) अपने संगठनों को अलगाववादी, विघटनकारी और आतंकवादी/हिंसक गतिविधियों को फेलाने के लिए संगठित करना,
- (ii) भारत की अखण्डता व राष्ट्रीय एकता के लिए हानिकार ताकतों के साथ साठ-गांठ करके राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों का खुलेतौर प्रचार करना,
- (iii) नागरिकों और पुलिस व सुरक्षा बलों के कर्मिकों को लक्ष्य बनाकर हत्या करने की वारदातों में अधिकाधिक शामिल होना,
- (iv) अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पार से और अधिक अवैध शस्त्र व गोलाबारूद प्राप्त करना,
- (v) अपनी गतिविधियों के लिए जनता से भारी मात्रा में धनराशि ऐंठना।

उपर्युक्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, केन्द्रीय सरकार का मत है कि ए.टी.टी.एफ. को तत्काल प्रभावी रूप से गैरकानूनी संगम घोषित करना आवश्यक है, और तदनुसार उक्त धारा 3 की उप-धारा 3 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निदेश देती है कि यह अधिसूचना उक्त अधिनियम की धारा 4 के अन्तर्गत दिए जाने वाले किसी भी आदेश के अध्याधीन सरकारी राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगी।

[एफ. सं. 9/11/97-एन. ई.-I]

जी. के. पिल्लै, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF HOME AFFAIRS

### NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd April, 1997

**S.O. 291(E).**—Whereas the All Tripura Tiger Force (hereinafter referred to as ATTF) has its professed aim, the formation of a separate nation of seven sisters comprising Tripura, Assam, Manipur, Mizoram, Nagaland, Meghalaya and Arunachal Pradesh resulting in bringing about the secession of the said States from the Indian Union, in alliance with other armed secessionist organisations of the North East region and to carry on armed struggle for separation of these States from the Indian Union and thereby secession of these States from Indian Union :

And whereas the Central Government is of the opinion that ATTF has—

- (i) been engaging in subversive and violent activities, thereby undermining the authority of the lawfully established Government and spreading terror and violence among the people for achieving its objective;
- (ii) established linkages with other unlawful associations, viz., United Liberation Front of Asom (ULFA) of Assam and the People's Liberation Army (PLA) of Manipur with the aim of mobilising their support;
- (iii) in pursuance of its aim and objective recently engaged in several violent and unlawful activities which are prejudicial to the sovereignty and integrity of India;

And whereas the Central Government is further of the opinion that violent and unlawful activities include—

- (a) killing of civilians and personnel belonging to the Police and Security Forces;
- (b) extortion of funds from the public including businessmen and traders in Tripura;
- (c) procuring large number of arms and ammunition, including sophisticated ones, through clandestine/illegal channels and inducting them secretly into Tripura through a neighbouring country;
- (d) establishing and maintaining camps in a neighbouring country for the purpose of safe sanctuary, training, procurement of arms and ammunition, etc;
- (e) establishing and maintaining linkages with other Tripura tribal extremist groups for causing and fomenting communal clashes between the tribal and non-tribal communities in Tripura.

And whereas the Central Government is of the opinion that the aforesaid activities of the ATTF are detrimental to the sovereignty and integrity of India and that it is an unlawful association;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967), the Central Government hereby declares the All Tripura Tiger Force (ATTF) as an unlawful association;

And whereas, the Central Government is also of the opinion that if there is no immediate curb and control, the ATTF will take the opportunity to—

- (i) mobilise its cadres for escalating its secessionist, subversive and terrorist/violent activities;
- (ii) openly propagate anti-national activities in collusion with forces inimical to India's sovereignty and national integrity;
- (iii) indulge in increased killings of civilian and targetting of Police and Security Forces personnel;
- (iv) procure and induct more illegal arms and ammunition from across the international border;
- (v) extort and collect huge funds from the public for its activities.

Having regard to the above circumstances, the Central Government is of the opinion that it is necessary to declare the ATTF as an unlawful association with immediate effect; and accordingly in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section 3 of the said section 3, the Central Government directs that the notification shall, subject to any order that may be made under section 4 of the said Act, have effect from the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No. 9/11/97-NE.I]

G.K. PILLAI, Jt. Secy.

#### अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 अप्रैल, 1997

**का.आ. 292(अ).**—जबकि नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा (इसके बाद इसे एन. एल. एफ. टी. कहा गया है) का घोषित लक्ष्य त्रिपुरा के अन्य सशस्त्र अलगाववादी संगठनों से समझौता करके सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से त्रिपुरा को भारत संघ से पृथक कराकर एक स्वतंत्र बोरोकलैंड त्रिपुरा का निर्माण करना और त्रिपुरा के मूल निवासियों को अलगाववाद के लिए उकसाना और उसके द्वारा त्रिपुरा का भारत संघ से अलगाव करना है,

जबकि केन्द्र सरकार की राय है कि एन. एल. एफ. टी.—

- (i) विध्वंसकारी और हिंसक गतिविधियों में लिप्त है, जिससे विधि द्वारा स्थापित सरकार की सत्ता को क्षति हो रही है और अपना लक्ष्य पूरा करने के लिए वह लोगों में आतंक और हिंसा फैला रही है,
- (ii) ने अन्य गैरकानूनी संगठनों अर्थात् नेशनल सोशलिस्ट कार्गिलिस्ट आफ नागालैण्ड (एन.एस.सी.एन.-1) के इजाक स्क्व गूट से उनका समर्थन प्राप्त करने के उद्देश्य से संपर्क स्थापित किया है,
- (iii) अपना लक्ष्य हासिल करने के लिए हाल ही में अनेक हिंसात्मक तथा गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल हुआ है जो भारत की प्रभुता और अखण्डता के प्रतिकूल है,

और जबकि केन्द्र सरकार की यह भी राय है कि हिंसात्मक तथा गैरकानूनी गतिविधियों में निम्नलिखित शामिल है :—

- (क) नागरिकों और पुलिस तथा सुरक्षा बलों के कार्मिकों की हत्या,
- (ख) त्रिपुरा में व्यावसायिकों तथा व्यापारियों सहित जनता से जबरन धन ऐंठना,
- (ग) गुप्त/गैरकानूनी माध्यमों से अत्याधुनिक हथियारों सहित बड़ी मात्रा में शस्त्र और गोलाबारूद प्राप्त करना और इन्हें किसी पड़ोसी देश के माध्यम से त्रिपुरा में गुप्त रूप से भेजना,
- (घ) सुरक्षित पनाह, प्रशिक्षण, हथियारों तथा गोलाबारूद की प्राप्ति के उद्देश्य से किसी पड़ोसी देश में शिविर लगाना और उनका संचालन करना,
- (ङ) त्रिपुरा में जनजातीय तथा गैर-जनजातीय समुदायों के बीच सांप्रदायिक दंगे करवाने तथा भड़काने के लिए त्रिपुरा के अन्य जनजातीय उग्रवादी समूहों के साथ संपर्क स्थापित करना और उसे बनाए रखना।

और जबकि केन्द्र सरकार की राय है कि ए.टी.टी.एफ. की उपरोक्त गतिविधियां भारत की संप्रभुता तथा अखण्डता के लिए खतरा है और यह एक गैर-कानूनी संगठन है,

अतएव, अब गैर-कानूनी गतिविधियां (निरोधक) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा घोषणा करती है कि ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स (ए.टी.टी. एफ.) एक गैर-कानूनी संगम है,

और जबकि केन्द्रीय सरकार का यह भी मत है कि यदि एन.एल.एफ.टी. पर तत्काल नियंत्रण नहीं लगाया जाता है तो उसे निम्नलिखित कार्यों के लिए अवसर मिल जाएगा—

- (i) अपने संगठनों को अलगाववादी, विघटनकारी और आतंकवादी/हिंसक गतिविधियों को फैलाने के लिए संगठित करना,
- (ii) भारत की अखण्डता व राष्ट्रीय एकता के लिए हानिकर ताकतों के साथ सांठ-गांठ करके राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों का खुलेतौर प्रचार करना,
- (iii) नागरिकों और पुलिस व सुरक्षा बलों के कार्मिकों को लक्ष्य बनाकर हत्या करने की वारदातों में अधिकाधिक शामिल होना,

- (iv) अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पार से और अधिक अवैध शस्त्र व गोलाबारूद प्राप्त करना,
- (v) अपनी गतिविधियों के लिए जनता से भारी मात्रा में धनराशि ऐंठना।

उपर्युक्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, केन्द्रीय सरकार का मत है कि एन.एल.एफ.टी. को तत्काल प्रभावीरूप से गैर-कानूनी संगम घोषित करना आवश्यक है, और तदनुसार उक्त धारा 3 की उप-धारा 3 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निदेश देती है कि यह अधिसूचना उक्त अधिनियम की धारा 4 के अन्तर्गत दिए जाने वाले किसी भी आदेश के अध्याधीन सरकारी राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगी।

[एफ. सं. 9/11/97-एन. ई.-1]

जी. के. पिल्लै, संयुक्त सचिव

#### NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd April, 1997

**S.O. 292(E).**—Whereas the National Liberation Front of Tripura (hereinafter referred to as NLFT) has its professed aim to establish an independent “Borokland Twipra” by liberation of Tripura from the Indian Union through armed struggle in alliance with other armed secessionist organisations of Tripura and incite indigenous people of Tripura, for secession and thereby the secession of Tripura from the Indian Union;

And whereas the Central Government is of the opinion that NLFT has—

(i) been engaging in subversive and violent activities, thereby undermining the authority of the lawfully established Government and spreading terror and violence among the people for achieving its objective;

(ii) established linkages with other unlawful associations, viz., the Isak Swu faction of National Socialist Council of Nagaland (NSCN-IM) with the aim of mobilising their support;

(iii) in pursuance of its aim and objective in the recent past, engaged in several violent and unlawful activities which are prejudicial to the sovereignty and integrity of India;

And whereas the Central Government is also of the opinion that violent and unlawful activities include—

(a) killing of civilians and personnel belonging to the Police Security Forces;

(b) extortion of funds from the public including businessmen and traders in Tripura;

(c) procuring large number of arms and ammunition, including sophisticated once, through clandestine/ illegal channels and inducting them secretly into Tripura through a neighbouring country;

(d) establishing and maintaining camps in a neighbouring country for the purpose of safe sanctuary, training, procurement of arms and ammunition, etc.;

(e) establishing and maintaining linkages with other Tripura tribal extremist groups for causing and fomenting communal clashes between the tribal and non-tribal communities in Tripura.

And whereas the Central Government is of the opinion that the aforesaid activities of the NLFT are detrimental to the sovereignty and integrity of India and that it is an unlawful association;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967), the Central Government hereby declares the National Liberation Front of Tripura (NLFT) as an unlawful association;

And whereas the Central Government is also of the opinion that if there is no immediate curb and control, the NLFT will take the opportunity to—

(i) mobilise its cadres for escalating its secessionist, subversive and terrorist/violent activities;

(ii) propagate anti-national activities in collusion with forces inimical to India's sovereignty and national integrity;

(iii) indulge in increased killings of civilians and targeting of Police and Security Forces personnel;

(iv) procure and induct more illegal arms and ammunition from across the international border;

(v) extort and collect huge funds from the public for its activities.

Having regard to the above circumstances, the Central Government is of the opinion that it is necessary to declare the NLFT as an unlawful association with immediate effect; and accordingly in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section 3 of the said section 3, the Central Government directs that the notification shall, subject to any order that may be made under section 4 of the said Act, have effect from the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No. 9/11/97-NE.-I]

G. K. PILLAI, Jt. Secy.